

उत्तराखण्ड राज्य (न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दंडति सदिधदोष बंदियों की सजामाफी/समयपूर्व मुक्तिके लिये) स्थायी नीति, 2022 की अधिसूचना जारी

चर्चा में क्यों?

12 दिसंबर, 2022 को उत्तराखण्ड की अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने उत्तराखण्ड राज्य (न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दंडति सदिधदोष बंदियों की सजामाफी/समयपूर्व मुक्तिके लिये स्थायी नीति, 2022 की अधिसूचना जारी की।

प्रमुख बंदि

- उत्तराखण्ड राज्य (न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दंडति सदिधदोष बंदियों की सजामाफी/समयपूर्व मुक्तिके लिये) स्थायी नीति, 2022 के अंतर्गत आजीवन कारावास में बंद महिला और पुरुष कैदी समान सजा के बाद रहि हो सकेंगे। रहिई के लिये उन्हें अच्छे आचरण, अपराध की प्रकृति और आयु की कसौटी पर परखा जाएगा। उनकी 50 हजार रुपए के नज्जी मुचलके पर रहिई हो सकेंगी।
- अपराध की प्रकृति के साथ बंदियों की रहिई पर नरिणय होगा। यदि कोई बंदी गलती से रहि हो जाता है तो उसे दोबारा जेल भेजा जा सकेगा। 13 से अधिक गंभीर बीमारियों से ग्रस्त बंदियों को भी रहिई मलि सकेगी।
- इस नीतिके तहत आजीवन कारावास के तहत अब अधिकतम 14 साल की सजा होगी। अभी तक महिलाओं के लिये 14 साल और पुरुषों के लिये 16 साल की सजा का प्रावधान था। लेकिन अब ऐसे सदिधदोष महिला व पुरुष बंदी जनिकी बनिा पैरोल के 14 साल और पैरोल के साथ 16 वर्ष की सजा पूरी हो गई है, उनकी सजा माफ हो सकेगी।
- इसी तरह 70 वर्ष से अधिक आयु के बगैर पैरोल वाले बंदी 12 वर्ष और पैरोल पर रहे 14 वर्ष और 80 वर्ष से अधिक उमर के कैदी बगैर पैरोल 10 वर्ष और पैरोल के साथ 12 वर्ष में रहि हो सकेंगे।
- नीतिके अनुसार ऐसे मामलों पर वचिर करने के लिये प्रमुख सचिव या सचिव गृह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी। इस कमेटी में प्रमुख सचिव या सचिव न्याय एवं वधिपिरामर्शी, प्रमुख सचिव या सचिव गृह और अपर सचिव गृह (कारागार) सदस्य होंगे, जबकि भिहानरीकषक कारागार सदस्य सचिव होंगे।